(ख) क्या किसी मकान नं० पर न तो चूल्हा टैक्स देने वाले का नाम बताया गया और न ही भूमि का ब्यौरा दिया गया जैसा कि उपरोक्त उल्लिखित अतारांकित प्रश्न के उत्तर में दी गई सूची के क्रम संख्या 8 में दर्शाया गया है कि मकान नं० 64-ए की भूमि और नाम तो बता दिया गया है परंतु 400 वर्ग गज से अधिक के मकान नं० 64 के मालिक और चूल्हा टैक्स देने वाले उनके पिता के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है और इसी प्रकार मकान नं० 77 और मकान नं० 71 के मामले में हुआ है तथा क्या इस प्रकार के और भी कई मामले हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम)** : (क) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार अड़कपुर बाग मोची के चूल्हा कर-दाताओं का सर्वेक्षण 4-6-86 को किया गया था सर्वेक्षण में, वहां रहने वाले चूल्हा करदाताओं और उनके उत्तराधिकारियों के नाम तथा आबादी में उनके कब्जे के क्षेत्र आदि की सूची बनाई गई थी। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि पुरानी आबादी में रह रहे किसी भी चूल्हा करदाता और उसके उत्तराधिकारी को सर्वेक्षण सूची में से छोड़ा नहीं गया है।

(ख) (और) (ग) आबादी के अंदर रह रहे सभी चूल्हा करदाताओं तथा उनके उत्तराधिकारियों के नाम सर्वेक्षण सूची में दर्ज किए गए थे। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि सर्वेक्षण के समय सर्वश्री मान सिंह, किशन चंद, रूप चन्द, और हरीश कुमार ने अपना मकान नंबर 64ए बताया था और उनके कब्जे वाले समग्र क्षेत्र को दर्ज किया गया था। अन्य मकान नं० 77/1 और 71 अड़कपुर बाग मोची की पुरानी आबादी में स्थित नहीं है। इसलिए, उनके नाम सूची में दर्ज नहीं किए गए थे।

**National Scheme for abolition of Scavenging**

3459. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether there was a scheme to identify scavengers in the country by 31st July, 1992, under the National Scheme for abolition of Scavenging;

(b) if so, the number of scavengers identified all over the country, State/Union Territory-wise; and

(c) what arrangements have been made to provide vocational training to them?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) and (b) Yes, Sir. The concerned State Governments/U.T. Administrations have been requested to undertake a rapid survey to identify each individual scavenger and his dependent and their apptitude for specified alternative trades/occupations. The survey is in progress in most of the States.

(c) It is proposed to provide training upto six months to the identified scavengers and their dependents in various trades/occupations through the existing training schemes of the Central and the State Governments.

**Waste water master plan for Cuttack**

3460. SHRI PRAVAT KUMAR SAMANTARAY: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether his Ministry has received a proposal from Government of Orissa under small activities scheme for waste water master plan of Cuttack proposed by Australian High Commission; and

(b) if so, what are the details of actions and decisions taken by Gov-